सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-21 7 से 21 नवम्बर, 2014 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

महान नवम्बर क्रान्ति जिन्दाबाद

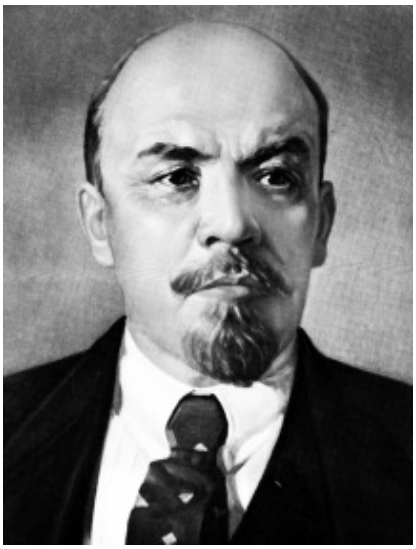

"क्रान्ति का बुनियादी नियम, जिसे सब क्रान्तियोंने और खासकर बीसवींसदी में होनेवाली रूस की तीनोंक्रान्तियों ने सही साबित कर दिया है, वह है: क्रान्ति के लिए इतना ही काफी नहीं है कि शोषित –उत्पीड़ित जनता पुराने ढंग से रहना असम्भव समझनेलगे और परिवर्तन की माँग करने लगे; क्रान्ति के लिए आवश्यक है कि शोषकोंके लिए भी पुराने ढंग से रहना और शासन करना असम्भव होजाए। जब "नीचेकेवर्ग" पुराना ढंग नहींचाहते और जब "ऊपर केवर्ग" पुराना ढंग नहींचला सक्ते–केवल उसी समय क्रान्ति की विजय होसकती है।"

– *लेनिन* *वामपंथी कम्युनिज़्म-एक बचकाना मर्ज़*

"विशेष संकट केरूप, क्रम, चित्र बदल गयेलेकिन संकट पूंजीवादी व्यवस्था का अवश्यम्भावी अंग बना रहा।... वह पूंजीवाद केबिगड़जाने –एकमायनेमेंव्यक्तिगत राजनैतिक और आर्थिक संकटोंऔर समूची पूंजीवादी व्यवस्था केपूर्णत: ढह जाने दोनोंही की ओर अग्रसर है– नये बड़े-बड़ेसत्यों द्वारा यह सुनिश्चित रूप से, खास तौर पर, और एक खास तौर पर बड़ेपैमाने पर स्पष्ट कर दिया गया है।"

– लेनिन *मार्क्सवाद और संशोधनवाद*

रसोई गैस मूल्य वृद्धि की एसयूसीआई(सी) ने की निन्दा

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 30 अक्तूबर को जारी एक बयान में कहा :

डीलरों के बढ़ाये कमीशन की वसूली के नाम पर घरेलू रसोई गैस के दामों में प्रति सिलेण्डर 3 रुपये की बढ़ोतरी करने के बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार के फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं। इससे यह साफ जाहिर है कि मोदी सरकार द्वारा 'अच्छे दिन' आने का जो वादा किया गया था, अन्तिम उपभोक्ता को अमुक-तमुक बहाने समय-समय पर ईंधन के दामों में बढ़ोतरी को सहन करना पड़ेगा ताकि अकूत मुनाफा लूटने वाली तेल कम्पनियों की तिजोरियां भरी जा सकें, लोगों के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ा जाएगा और उन्हें और भी कंगाल बना दिया जाएगा।

लोगों से हम आह्वान करते हैं कि वे उन पर बार-बार हो रही ऐसी आर्थिक मार को हताश होकर स्वीकार न करें, लामबंद हों और अपनी संगठित आवाज बुलन्द करें।

सीपीआई(एम) महासचिव के साथ वार्ता के बाद पत्रकार सम्मेलन में कॉमरेड प्रभाष घोष का वक्तव्य

(कोलकाता में 18 अक्टूबर को सीपीआई(एम) के महासचिव कॉमरेड प्रकाश करात के साथ वार्ता के बाद पत्रकार सम्मेलन में एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्न वक्तव्य दिया)

गत अगस्त महीने में सीपीएम के राज्य सचिव विमान बोस ने हमारे साथ बात करना चाहा और हमारी बातचीत हुई भी। वाम पार्टियों के आह्वान पर 1 सितम्बर को होने वाली साम्राज्यवाद-विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने हमें बताया था। जब पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) सत्ता में थी और हम उनकी सरकार के खिलाफ आन्दोलन संगठित कर रहे थे तब भी साम्राज्यवाद-विरोधी और बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद साम्प्रदायिकता-विरोधी कम से कम 5 संयुक्त प्रोग्रामों में उनके साथ हमने हिस्सा लिया था। इसलिए, इस बार भी हमने शामिल होने पर सहमति जताई।

इसके कुछ दिन बाद विमान बोस ने मुझे बताया कि उनके महासचिव प्रकाश करात मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि श्वासकष्ट के साथ ही मैं चिरकालिक दमे का रोगी हूँ और कई बार निमोनिया से ग्रस्त हुआ हूँ, अत: जलवायु परिवर्तन के इस दौरान मेरे लिए दिल्ली जाना सम्भव नहीं होगा। अपने दिल्ली कार्यालय से सलाह मशवरे के बाद विमान बोस ने मुझे बताया कि कॉमरेड प्रकाश करात मुझसे मिलने के लिए कलकत्ता आना चाहते हैं। दिल्ली में प्रकाश करात ने हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती के साथ प्रारंभिक बातचीत की थी। 16 अक्टूबर के लिए हमारी मीटिंग तय हुई थी। मैं और हमारे पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर सीपीआई(एम) कार्यालय में उनके साथ बैठे थे। सीपीआई(एम) महासचिव ने ठोस रूप में हमारे सामने

पत्रकार सम्मेलन में कॉ. प्रभाष घोष। उनके बाईं ओर कॉ. रंजीत धर और दाहिने ओर कॉ. सोमेन बोस

प्रस्ताव रखा कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ सर्वभारतीय स्तर पर हमारे साथ मिलकर वे व्यापक वाम एकता कायम करना चाहते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर और एकाधिकारी पूँजी के स्वार्थ में नव-उदारवादी नीति के तौर पर जो सब आर्थिक हमले बीजेपी सरकार चला रही है इनके खिलाफ जैसे कि हम वामपंथी एकजुट होकर अभियान चला सकें यह भी उनका प्रस्ताव था। इसी उद्देश्य से आगामी 1 नवम्बर को दिल्ली में 6 पार्टियों– सीपीआई(एम), एसयूसीआई(सी), सीपीआईएमएल (लिबरेशन), सीपीआई, फार्वर्ड ब्लॉक, आरएसपी को लेकर बैठक करने का प्रस्ताव भी उन्होंने दिया। अन्य किसी भी पार्टी या शक्ति को इस एकजुटता के अन्दर शामिल किया जाए या नहीं यह भी ये 6 पार्टियाँ बातचीत करके तय करेंगी। कुछ और बिन्दुओं को लेकर अंतिम घोषणा पत्र और एक मांगपत्र 1 नवम्बर को दिल्ली में जारी किया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

प्रभाष घोष का वक्तव्य ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जाएगा। कॉमरेड करात ने एक ड्राफ्ट हमें दिया है, हमारे और अन्य सभी के विचारों को समाहित करते हुए 1 नवम्बर को इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

मैने सीपीआई(एम) के नेताओं को बताया कि समाजवादी खेमे के ध्वस्त होने, विश्व साम्यवादी आन्दोलन में पूरी तरह अफरातफरी और भारत में वाम आन्दोलन के अभाव के चलते ही आज वामपंथ का यह संकट पैदा हुआ है। अत: अखिल भारतीय स्तर पर वामपंथियों को एकजुट होने की जरूरत बहुत दिनों से ही थी। इसके लिए हमारी पार्टी निरन्तर प्रयास भी करती रही है। इस एकजुटता में क्षेत्रीयतावादी, संकीर्णतावादी और जात-पात आधारित पार्टियों को शामिल करने का सवाल ही नहीं उठता है।

भारत में अभी जो खतरा दिखाई दे रहा है, हमारी पार्टी का मानना है कि सिर्फ दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों का खतरा कहने से उसके गम्भीर चरित्र को समझा नहीं जा सकता है। भारत में, लम्बे अर्से से कांग्रेस के शासनकाल से ही प्रशासनिक फासीवाद चल रहा है। भारतीय पूँजीवाद बहुत पहले ही एकाधिकारी पूँजीवाद के स्तर पर पहुँच चुका है। जिसका मायना है चन्द हाथों में पूँजी का संकेन्द्रण। भारतीय राजसत्ता बहुत पहले ही एकाधिकारी पूँजी के स्वार्थों की सेवादार बन चुकी है। भारत आज वस्तुत: इण्डस्ट्रीयल-मिलिट्री-ब्यूरोक्रेटिक गठजोड़ द्वारा शासित है और इसके हाथों में ही तमाम शक्तियाँ केन्द्रित हो गई हैं। ये तमाम फासीवाद के आर्थिक और राजनीतिक आधार का काम करते हैं और कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ समाज में विचारों और चिन्तन के क्षेत्र में आध्यात्मवाद व मध्ययुगीन विचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जबकि विज्ञान के तकनीकी पहलुओं पर ही सिर्फ जोर दिया जा रहा है। इसका घृणित उद्देश्य है लोगों की तर्कसंगत और वैज्ञानिक मानसिकता को नष्ट कर देना। यह फासीवाद के आगमन को ही तेज करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के शासनकाल से ही भारत में फासीवाद के बढ़ने का जो खतरा लगातार मंडरा रहा है अब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यह खतरा और भी बढ़ गया है। बीजेपी-नीत सरकार की मदद और सहयोग से आरएसएस अपने अनिष्टकारी विचारों, साम्प्रदायिक नफरत और दंगों के संदेशों को देश भर में फैला रहा है और इसे रोकने के लिए व्यापक पैमाने पर आन्दोलनों और वैचारिक संघर्षों की जरूरत है।

सीपीआई(एम) के नेताओं को हमने बताया कि कांग्रेस का नजरिया कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता के मायने को विकृत करके सभी धर्मों को प्रोत्साहन देना बना दिया। छद्म धर्मनिरपेक्षता के नारे के आवरण में खुद को छिपाते हुए कांग्रेस ने असल में प्रत्यक्ष या परोक्ष साम्प्रदायिकता पर ही अमल किया है। जबकि बीजेपी खुल्लमखुल्ला एक साम्प्रदायिक पार्टी है। बीजेपी का जो सैद्धान्तिक अभिभावक आरएसएस है वह तो हिन्दुत्ववादी साम्प्रदायिकता पर ही आधारित है, उसका तो ऐजेण्डा ही यह है। इसलिए खतरा और भी बढ़ गया है।

आर्थिक क्षेत्र पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा ही भारतीय और विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सेवा की है। तथाकथित नव-उदारवादी नीतियाँ जो और कुछ नहीं बल्कि देशी और विदेशी पूँजीपति वर्ग के हितों को साधने के ही हथियार हैं। ये भी कांग्रेस द्वारा ही लागू की गई थी। लेकिन पूँजीपति वर्ग और भी तेजी से इन नीतियों को लागू करने की मांग कर रहा था जिसमें गठबंधन सरकार की मजबूरियों की वजह से कांग्रेस नाकाम हो रही थी। इसके अलावा, अपने भ्रष्ट और जन-विरोधी चरित्र के चलते कांग्रेस तेजी से जन समर्थन खोती जा रही थी। ऐसी एक परिस्थिति में देशी और विदेशी एकाधिकारी पूँजीपतियों ने बीजेपी और नरेन्द्र मोदी को चुना और उन्हें सत्ता में ला दिया। इसलिए, मोदी, कांग्रेस से बेहतर कॉरपोरेटों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसने अपनी सरकार की नीतियों और कदमों द्वारा पहले ही इसे सिद्ध कर दिया है। इसके साथ-साथ बीजेपी-आरएसएस गठजोड़ हिन्दुत्व की अपनी जहरीली विचारधारा के खूँखार पंजों को फैला रहा है जो भारतीय नवजागरण के योगदानों और उपलब्धियों को तहस-नहस कर देना चाह रहा है। यदि वे सफल होते हैं तो जो थोड़ा बहुत भी तार्किक मनोभाव, जनवादी मूल्यबोध और चिन्तन, वैज्ञानिक मनन हमारे समाज में बचा है वह भी ध्वस्त हो जाएगा।

मैंने उनको यह भी बताया कि साम्प्रदायिकतावाद-विरोध का मायने स्वयंमेव ही धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का असल मायने है राजनीति, राजसत्ता, शिक्षा और कानूनों के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं रहेगा। धर्म एक नागरिक का निजी मामला रहेगा। धर्मविश्वासियों और धर्म में विश्वास न करने वाले दोनों तरह के लोगों को राजसत्ता समान दृष्टि से देखेगी। यूरोपीय नवजागरण विश्व में इस जनवादी विचार को आधुनिक जनवादी राज्य की एक बुनियादी शर्त के रूप में लाया था। लेकिन यहाँ भारत में कभी भी इसका अनुसरण नहीं किया गया। परिणामत: धर्मांधता, साम्प्रदायिकता, जातिवाद आदि संकीर्ण लाइनों पर लोगों को बांटने के जरिए चुनावों में लाभ बटोरने की खातिर धूर्त और बदमाश राजनीतिक ताकतों के शस्त्रागार में ये सुलभ हथियार बन गए हैं। आरएसएस-बीजेपी के सत्ता में आने से लोगों की एकता को खतरा भयंकर रूप से बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए धार्मिक कट्टरता और आध्यात्मवादी चिन्तन और विचारों के खिलाफ सशक्त सैद्धांतिक आन्दोलन गठित करने होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने सत्ता में आते ही मजदूर वर्ग, किसान समुदाय और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर निरन्तर आर्थिक हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के खिलाफ केवल सम्मेलनों, मीटिंगों और प्रचार से काम नहीं चलेगा, राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर सुसंगठित वर्ग और जन संघर्ष गठित करने होंगे। वामपंथियों की एकता और काम का आधार यही होना चाहिए।

मैंने व्याख्या करके बताया कि वामपंथी एकता के पक्ष में हम हमेशा रहे और हैं। मैंने प्रकाश करात को बताया कि आपके साथ पहले परिचय नहीं हुआ था, हो सकता है आपकी जानकारी में न हो, आजादी के बाद 50 के दशक में जब इसी पश्चिम बंगाल में वामपंथी आन्दोलन हुआ तब सीपीआई को दूसरी-दूसरी पार्टियाँ वाम एकता में शामिल करना नहीं चाहती थी। उस समय आरएसपी, फार्वर्ड ब्लॉक आरसीपीआई बहुत ताकतवर पार्टियाँ थी। अगस्त 1942 के आन्दोलन के विरोध में सीपीआई की भूमिका, नेताजी और आईएनए को जापान का दलाल बताना, 1948 में रणदिवे की अल्ट्रा लेफ्ट लाइन आदि को लेकर जो मतभेद और कड़वाहट पैदा हुई थी, इन सब वजहों से आरएसपी, फार्वर्ड ब्लॉक और अन्यान्य वामपंथी पार्टियाँ सीपीआई को संयुक्त आन्दोलन में नहीं चाहती थी। उस समय हमारी पार्टी के संस्थापक, हमारे शिक्षक मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था, सीपीआई को छोड़कर संयुक्त आन्दोलन नहीं हो सकता है। सुरेश बैनर्जी उस समय के जानी-मानी हस्ती थे एक जाने-माने जन नेता थे। अकाल प्रतिरोधी कमेटी के बैनर तले जो खाद्य आन्दोलन चल रहा था, उस कमेटी के वे चेयरमैन थे। सीपीआई तब एक अन्य बैनर तले अलग कमेटी बना कर चल रही थी। हमने सुरेश बाबू को समझाया कि सीपीआई को छोड़कर संयुक्त आन्दोलन नहीं हो सकता है, वे राजी हुए, सीपीआई को शामिल कराया गया। इसके बाद लगातार 1970 तक पहले सीपीआई, बाद में जब 1964 में सीपीआई(एम) बनी, तब उनके साथ हमारी एकजुटता रही और महत्वपूर्ण आन्दोलन हुए थे। जहां विभिन्न सवालों को लेकर हमारे मतभेद होते थे वहीं एकजुटता भी थी। मतभेद के बिन्दुओं पर हम अपना वक्तव्य रखते थे। 1967 व 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार गठन के समय हमारे साथ गंभीर मतभेद हुए थे। हमने कहा था कि संयुक्त मोर्चा सरकार को वर्ग संघर्ष और जन संघर्ष का हथियार बनाना होगा। मजदूर-किसान-मध्यम वर्गीय जनता के हित में वर्ग संघर्ष व जनआन्दोलन को तीव्रतर करना ही इस सरकार का लक्ष्य होगा। एक बुर्जुआ सरकार की तरह संयुक्त मोर्चा सरकार कार्य नहीं कर सकेगी। जनआन्दोलन का दमन करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करना नहीं चलेगा। इस सवाल पर सीपीआई(एम) और अन्यान्य पार्टियों के साथ हमारा मतभेद शुरू हुआ था।

1970 में वर्ग आधारित फ्रण्ट का नारा उठाकर सीपीआई(एम) ने संयुक्त मोर्चा भंग कर दिया। तब हमारी पार्टी के साथ भी एकता टूट गई। 1971 में हमने आठ पार्टियों का मोर्चा बनाया जिसमें हमारे साथ सीपीआई और फार्वर्ड ब्लॉक थी। सीपीआई(एम) तब 6 पार्टियों के साथ एक अन्य गठजोड़ में थी। 1972 में पुन: सीपीआई(एम) ने 9 पार्टियों के गठजोड़ में हमारे साथ मोर्चा बनाया 1974 तक यह मोर्चा था। 1974 में इन्दिरा कांग्रेस सरकार-विरोधी जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को केन्द्र करके मतभेद दिखाई दिए। हमने तब कहा था कि जेपी आन्दोलन की मांगें डैमोक्रेटिक हैं, आन्दोलन भी डैमोक्रेटिक है, जनसंघ और अन्यान्य दक्षिणपंथी मौके का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि वामपंथी इस आन्दोलन में नहीं हैं। हमने कहा कि हम वामपंथी इस आन्दोलन में शामिल होकर विकल्प नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सीपीआई ने खुल्लमखुल्ला इंदिरा कांग्रेस को समर्थन दे दिया और सीपीआई(एम) विभिन्न कारण दिखाते हुए आन्दोलन में शामिल नहीं हुई। इसके फलस्वरूप पूरे आन्दोलन को इस्तेमाल करते हुए जनसंघ अपनी ताकत बढ़ाने में सफल हुई। इस सवाल को लेकर हमने सीपीआई(एम) की आलोचना की। तब सीपीआई(एम) ने हमसे कहा, 'आप लोग संयुक्त आन्दोलन में रह कर हमारी आलोचना कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते'। हमने कहा, संयुक्त आन्दोलन संचालन में एकता-संघर्ष-एकता-यही तो मार्क्सवादी नजरिया है। साझे दुश्मन के खिलाफ एकजुट रहते हुए अपने अन्दर वैचारिक संघर्ष संचालित करना और इसी रास्ते अपने अन्दर समझदारी बढ़ाते हुए एकता को मजबूत करना-यही तो सटीक नजरिया है। सीपीआई(एम) के नेताओं ने हमारी इस बात को स्वीकार नहीं किया और हमारे साथ एकता को भंग कर दिया। 1974 से सीपीआई(एम) के साथ हमारी एकता नहीं है।

1977 में सीपीआई(एम) पश्चिम बंगाल में सरकारी सत्ता पर काबिज हुई। सरकार ने गैर-वाम और जनविरोधी नीतियाँ अपनानी शुरू कर दी। उसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हमने जोरदार जनआन्दोलन का रास्ता अपनाया। मैने संक्षेप में यह इतिहास प्रकाश करात को बताया। फिर यह भी उन्हें याद दिलाया कि जब हम पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) सरकार के खिलाफ निरन्तर आन्दोलन कर रहे थे तब भी हमने अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआई(एम) के साथ केन्द्रीय सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त आन्दोलन करना चाहा था। उस समय सीपीआई(एम) के नेतृत्व को यह बताया भी गया था। तब उन्होंने हमारे सामने यह शर्त रखी कि 'पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) सरकार के खिलाफ आप आन्दोलन बन्द करो तभी अखिल भारतीय एकता होगी।' हमने कहा यह हमारे लिए संभव नहीं है। इसी वजह से अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआई(एम) के साथ तब हमारी एकजुटता नहीं हुई। ये सब बातें स्पष्ट रूप से प्रकाश करात को बताई गई। यह भी हमने कहा कि सिंगूर-नन्दीग्राम आन्दोलन के आधार पर जब हमने तृणमूल के साथ एकजुटता की थी तब भी हमारी पहली शर्त थी कि मार्क्सवाद और वामपंथ पर तृणमूल हमला नहीं करेंगी। तृणमूल ने इस शर्त को मान लिया था और इस पर अमल करने के लिए मजबूर हुई थी। अन्य शर्तों पर उसने अमल नहीं किया था। हमने यह भी बता दिया था कि तृणमूल जब भी सरकार में जाएगी हम सड़क पर उतर कर उसके खिलाफ वामपंथ का झण्डा लेकर आन्दोलन करेंगे। उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। इसलिए हम हमेशा ही वाम एकता के पक्ष में थे और हैं। यही निरन्तर हमारी राजनीतिक लाइन रही है। यदि आप वाम आन्दोलन के प्रति गंभीर हैं और वामपंथ के आधार पर वर्ग संघर्षों और जनसंघर्षों का निर्माण करना चाहते हैं तब हम इस एकता के पक्ष में हैं। लेकिन हमने प्रकाश करात को बता दिया था कि केरल राज्य इसका अपवाद होगा क्योंकि वहाँ हम पहले से ही दो अन्य लेफ्ट पार्टियों-आरएमपी और एमसीपीआई के साथ एक संयुक्त मोर्चे में हैं। इसलिए केरल में हम सीपीआई(एम) के साथ संयुक्त आन्दोलन में नहीं जा सकते हैं।

अब पश्चिम बंगाल की परिस्थिति के बारे में विमान बोस की उपस्थिति में ही मैने बताया कि यहाँ उनकी सरकार के खिलाफ आन्दोलन करते समय या तो सीपीआई(एम) के बदमाशों द्वारा नहीं तो पुलिस गोलीबारी में हमारे 161 कॉमरेड मारे गए हैं हमारे 49 कॉमरेड झूठे केसों में आजीवन कारावास का दण्ड भोग रहे हैं। मैं खुद अपने सहयोगियों के साथ उसी समय आपके इसी सीपीआई(एम) कार्यालय में विमान बोस के पास आया था और बाद में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने हम राईटर्स बिल्डिंग गए थे। मैंने उन्हें बताया था कि जो मारे जा रहे हैं वे हमारी पार्टी के लीडर और कैडर हैं। हम वेतन देकर कार्यकर्ता भर्ती नहीं करते हैं। ये एक आदर्श से प्रेरित हो कर राजनीति में आए हैं, ये समाज के अनमोल बेटे-बेटियाँ हैं और आपकी पार्टी के लोग उन्हें मार रहे हैं। आप यह सब बंद करिए। लेकिन इन दोनों ने हत्याएं रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए पश्चिम

(शेष पृष्ठ 7 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति

शिवदास घोष

(गतांक से आगे)

आन्दोलनों के सामने सही मूल राजनैतिक लाइन होना जरूरी है

नवम्बर क्रान्ति से अनेक सीखें हासिल होती हैं लेकिन वे सब एक ही चर्चा से पूरी नहीं की जा सकती हैं। हमारे देश में मूल राजनैतिक सवाल पर ही काफी भ्रम व्याप्त है। हम लोग भूल-भुलैया में भटके हुए हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ़ रहे हैं। सही रास्ता पाने के लिए अगर हमें उस चीज से बाहर निकलना है तो हमें नवम्बर क्रान्ति के बुनियादी सबक को आत्मसात करना होगा। हमें समझना होगा कि अगर आन्दोलन के सामने एक सही मूल राजनैतिक लाइन निर्धारित नहीं हो पाती, तो अतीत के अनगिनत संघर्षों की तरह उत्पीड़ित जनता के मुक्तिकामी संघर्ष भविष्य में भी बार-बार लाजमी तौर पर व्यर्थ हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि क्रान्ति करने की शक्ति इस देश में नहीं है, जनता में क्रान्ति के लिए संकल्प और उत्साह नहीं है, नौजवानों में संघर्ष करने की फितरत नहीं है, वे प्राणों का उत्सर्ग नहीं कर सकते हैं, मजदूर-किसानों में जीजान से लड़ने का माद्दा नहीं है, संघर्ष के लिए कुछ भी त्याग कर सकने की क्षमता नहीं है–वे इतिहास को नकारते हैं। मैं कहता हूँ कि यह सच नहीं है। इस देश के किसान-मजदूर, मेहनतकश, अनगिनत मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र-नौजवान बार-बार आन्दोलन में कूदे हैं। ''शोषकों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, हमें क्रान्ति करनी है''–जब कभी, सही वक्त पर जिस किसी ने भी, भले ही उसका संगठन छोटा हो, यह नारा दिया, हमने देखा कि लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर उल्लास के साथ उसका स्वागत किया है, और देश को आन्दोलनों की लहरों में सरोबार कर दिया है। ''हम क्रान्ति चाहते हैं'' –केवल इसी ललक ने, इसी स्वप्न ने नौजवानों को हर बार संघर्षों की खातिर जान जोखिम में डालने की प्रेरणा दी है। क्रान्ति होती क्या है, कहां होगी, कैसे होगी, किसके नेतृत्व में होगी, उसकी सही दिशा क्या होगी–इन सब ठोस सवालों को लेकर उन्होंने सर नहीं खपाया।

हमारे देश के लड़के लड़ना नहीं चाहते, हमारे देश के किसान-मजदूर स्वभावतः संघर्ष के प्रति अनिच्छा रखते हैं, वे रूस, चीन और वियतनाम के किसान-मजदूरों और नौजवानों जैसे दिलेर, लड़ाकू नहीं हैं, क्रान्ति के प्रति उन जैसा जीवन-मरण का समर्पण नहीं है, अगर कोई उनके लिए इत्तिफाकन क्रान्ति ले आये तभी हमारे देश के नौजवान और किसान-मजदूर क्रान्ति चाहेंगे अन्यथा वे स्वभाव से दब्बू हैं और लड़ाई-झगड़े, झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं– ये सब बातें सच नहीं हैं। असली समस्या कहीं और है। असली समस्या यह रही कि उनके सामने सही रास्ता नहीं था, सही मूल राजनैतिक लाइन का अभाव था। और अगर रास्ता सही तरह से प्रशस्त न हो, आन्दोलन का रणकौशल, उसका उद्देश्य और लक्ष्य तय करने के सम्बन्ध में सही धारणा न हो, अगर क्रान्ति की रणनीति ठीक-ठीक निर्धारित न की गई हो यानी मूल राजनैतिक लाइन और आन्दोलन का उद्देश्य ही सही न हो, तो लड़ने, मर मिटने का चाहे कितना ही जीवट क्यों न हो, कुर्बानी करने कर सकने का दमखम क्यों न रहे, उनकी तमाम शहादतें बरबाद जायेंगी। लेकिन क्या यह शहादत केवल उसी वक्त के लिए व्यर्थ जाती है? क्या यह हकीकत नहीं है कि इस विफलता के असर से आन्दोलनकारियों के दिलो-दिमाग पर निराशा-हताशा छा जाती है। आन्दोलनों और संघर्षों के प्रति वे संदिग्ध हो उठते हैं, उनमें अविश्वास पैदा हो जाता है। ''देखो कितना लड़े, कितनी जानें गवांई, इतनी क्षति उठाई, क्या कुछ नहीं किया हमने, लेकिन हमें मिला क्या? यही उनके दिमाग को परेशान किये रहता है। वामपंथी दलों के राजनैतिक कार्यकर्ताओं से वे पूछते हैं, ''आन्दोलन को तो हमने समर्थन जुटाया था, जानें भी हमने गवांई लेकिन अंजाम क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता इस देश में। उफ, आप सबको काफी देख-परख लिया, राजनैतिक दलों को भी देख लिया। आप सभी एक जैसे हैं। आप में से कोई भी, कोई भी दल कुछ भी नहीं कर सकता।'' आन्दालनों की नाकामयाबी के परिणामस्वरूप हताशा की एक मानसिकता लोगों के

मन-मस्तिष्क को आच्छन्न कर लेती है।

इन कड़ुवे अनुभवों से लोग बहुधा मामूली सवालों पर भी चकरा जाते हैं–आजकल इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं विस्तारपूर्वक इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। चलो उनकी यह बात मान लें कि हम में से कोई भी, कोई भी दल कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मायने क्या हुआ? क्या आपको कुछ नहीं करना है? आपने हम सबको अस्वीकार कर दिया है, तो क्या जिस ढंग से आप अपना जीवन जी रहे हैं, वह उचित है? क्या आप ऐसा ही करते रहेंगे? क्या इससे भूख मिटेगी? चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, नौकरी भी सुरक्षित नहीं है, जमीन से बेदखली जारी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, परिवार टूट रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सुख-चैन नहीं है, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति सब नीरस हो गए हैं, लड़के-लड़कियाँ आँखों के सामने दिन प्रतिदिन मनमौजी और निरंकुश होते जा रहे हैं, आप स्वयं भी तो गिरते जा रहे हैं वह आप भी जानते हैं–तब क्या आप इसे यूँ ही चलते हुए देखना पसंद करेंगे? नहीं, इस ढंग से निश्चित ही ज्यादा दिन नहीं चल सकता। कभी-कभी उनमें सुप्त पुरुषार्थ जागृत हो उठता है। इन्सानियत का फर्ज अगर उन्हें न भी झकझोरता हो, तब भी अपने जीवन की विकट स्थितियों को वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि यह पेट एक बड़ी बला है, एक कठोर सच्चाई है। ऊँचे चेतनाबोध के अभाव में, नीति-नैतिकता का स्तर ऊँचा न रहने से, हो सकता है कि इन्सानियत के तकाजे का ख्याल नहीं रख पाते, पर पेट की ओर से बेफिक्र वे नहीं रह सकते। इसलिए हार कर भी उन्हें फिर उठ खड़ा होना है। लेकिन जब वे उठ खड़े होते हैं, तो वे या तो उन्माद में आकर प्रतिक्रिया करते हैं या बच्चों जैसी हरकतें करते हैं –अधीरता और बेतरतीबी से भरी। क्योंकि आन्दोलनों के लिए जरूरी संगठन का नेटवर्क कहाँ है? सही राजनैतिक नेतृत्व कहाँ है? हर पाँच सात साल में, आठ दस वर्षों के अंतराल में देश में आन्दोलन का एक ज्वार आता है और हर संघर्ष में पराजय के बाद लोगों में निराशा-हताशा घर कर लेती है। उन्हें यह लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये ही थके-हारे पराजित लोग कुछ समय बाद फिर बेचैन हो उठते हैं और परिवर्तन के लिए तड़प उठते हैं। संघर्ष में तो उन्हें उतरना ही होगा, इससे बचने का कोई जरिया नहीं है। आज या दो साल बाद, नहीं तो पांच साल बाद उन्हें संघर्ष में सम्मिलित होना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे संघर्ष में उतरते हैं, वे बचकानी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध कोई भी राह पकड़ लेते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं और इस विश्वास के साथ कि वे क्रान्ति करने जा रहे हैं अपने आपको लड़ाई में झोंक देते हैं, भले ही उनकी जान चली जाए। लेकिन पुनः वे पराजित होते हैं, गलत रास्ते भटक जाते हैं। इसीलिए हर आन्दोलन के सामने नवम्बर समाजवादी क्रान्ति की यह बुनियादी सीख हमें रखनी ही होगी।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी दसवीं पार्टी कांग्रेस में नवम्बर क्रान्ति की इस अमूल्य सीख को अपने तरीके से बड़ी प्रांजलता के साथ रखा है। चाहे कोई कितना भी असीम क्षमतावान और प्रभावशाली व्यक्तित्व का अधिकारी हो, विचारधारा और मूल राजनैतिक लाइन गलत रहने से अंततः सब कुछ खो देगा। 'विचारधारा' शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। मूल्यबोध और सिद्धान्त नीति-नैतिकता, रूचि-संस्कृति और आन्दोलन से संबंधित तमाम सवालात इसी 'विचारधारा' शब्द में निहित हैं। हमारे देश में आन्दोलनों में एक विशेष रुझान काम कर रहा है, वह है, लोग लड़ने-मरने को तैयार हैं, नारे लगाते हैं लेकिन अपनी जबान पर जरा भी लगाम लगाने को तैयार नहीं, नीति-नैतिकतागत मूल्यों और संस्कृति की परवाह नहीं, उन्हें संयम से क्या लेना-देना, उन्हें शालीन और सौम्य आचरण से कोई सरोकार महसूस नहीं होता –आन्दोलनों को इस तरह की झोंक से बड़ा नुकसान हो रहा है। जो लोग आन्दोलन करते वक्त इस ढंग से आचरण करते हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें किसी भी ढंग से मनमर्जी से बोलने का अधिकार है, गाली-गलोज देकर अपनों से बड़ों का अपमान करने का अधिकार है, सड़क पर नारे लगाते समय फूहड़ता से मटकने-लचकने में उनका कोई दोष नहीं है–क्रान्ति तो होगी ही क्योंकि वे नारे जो लगा रहे हैं, वे क्रान्ति का आह्वान जो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। चूँकि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए नारों से वे आन्दोलनों की तरफ आकर्षिक हो सकते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र टिप्पणियों और अश्लील भाव-भंगिमाओं को देख कर लोगों को डर लगने लगता है। उनकी घोर खुदगर्जी को देख कर लोग उनसे दूर भागते हैं। फलस्वरूप लोगों में आन्दोलन के औचित्य के प्रति ही संशय और अविश्वास पैदा हो जाता है।

इस सिलसिले में एक बात और याद रखना जरूरी है। महज पार्टी की संगठनात्मक ताकत के जरिए क्रान्ति नहीं होती। क्रान्ति के लिए न केवल लाखों लाख लोगों का एक फौलादी संगठन चाहिए बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि संगठन के बाहर मौजूद देश की विशाल जनता के एक बड़े तबके को क्रान्ति का कम से कम परोक्ष समर्थक बनाया जाए। अगर वे परोक्ष समर्थक न भी बन सकें तो कम से कम क्रान्ति के निष्पक्ष हितैषी ही बने रहें ताकि वे क्रान्ति के खिलाफ न जाएं। क्रान्ति की सफलता के लिए यह न्यूनतम शर्त है। मान लो कि अनुमानतः क्रान्तिकारी समेत सभी पार्टियों की कुल संगठनात्मक क्षमता पांच लाख है, तब भी देश की जनसंख्या की तुलना में यह संख्या बिल्कुल नगण्य सी है। इसलिए अगर हम गंभीर नहीं है और नीति-नैतिकतागत मूल्यों से हमारा कोई सरोकार नहीं है और न ही शालीनता, चरित्र, शिष्टाचार और मर्यादा के प्रति हमारी कोई धारणा है तो हम इतने विशाल जन समुदाय के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करेंगे और छिन्न मूल हो जाएंगे।

लिहाजा, विचारधारा से हमारा अभिप्राय बाहर से आयातित शब्दजाल और गुंजायमान नारों से नहीं है। नीतिगत मूल्यबोध एवं संस्कृति, आन्दोलन की नैतिकता और सिद्धान्त, चरित्र की मर्यादा और शालीनता ये सब विचारधारा में आते हैं। जो लोग आन्दोलन में भाग लेते हैं, आन्दोलनों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, वे जनता के बीच रहते हैं। जिस तरह एक अफवाह फैलती है, अखबारों के जरिए नहीं, गपशप और कानाफूसी के जरिए, मसलन कलकत्ता से लेकर दूर दराज के इलाकों बांकुड़ा तक फैल जाती है। अगर वे सोचें कि लोग बाग उनके व्यक्तिगत जीवन में झाँकने तो आ नहीं रहे, तब चाहे जिस तरह का जीवन यापन करने में वे स्वतंत्र हैं और क्रान्ति तो मैदानों, मंचों से भाषण देने से आ ही जाएगी, उन्हें याद रखना चाहिए, यह इतना सीधा-सरल नहीं है। कहीं भी इस तरह क्रान्ति नहीं आई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस सत्य को बार-बार दोहराया है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

उन्होंने कहा कि अगर आपकी विचारधारा गलत है, अगर आपकी मूल राजनैतिक लाइन गलत है, तो आज आप कितने भी ताकतवर क्यों न हों, यह बहुत समय तक टिकेगी नहीं। केवल ताकत के बलबूते आप क्रान्ति नहीं ला सकते बल्कि उससे तो आप भारी नुकसान ही पहुँचाएंगे। उन्होंने लिन प्याओ का ठोस उदाहरण देकर समझाया है कि लिन प्याओ ने राजसत्ता, पार्टी और सेना पर अनाधिकार कब्जा कर लिया था, लेकिन वह कुछ भी संभाल नहीं सका। क्योंकि जिस मूल राजनैतिक लाइन, विचारधारा, सिद्धांत, संस्कृति, नीति-नैतिकता और जीवन मूल्यों को लेकर वह चल रहा था, वे ही सही नहीं थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छल-कपट, मिथ्यावाद लम्बे समय तक नहीं टिकने का। जनता की निम्न स्तर की चेतना का फायदा उठाकर, उनकी मनीषा के तार्किक रुझान को भोथरा करते हुए आप कुछ समय तक कपट के सहारे राज कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। इन ठोस घटनाओं से हमें सबक सीखना होगा।

मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्यम्भावी है

इससे पहले कि मैं नवम्बर समाजवादी क्रान्ति पर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को, जिनकी भाषण के दौरान में चर्चा कर चुका हूँ, पुनः संक्षेप में रखना चाहूँगा जिससे यहाँ सभा में आए मजदूर-किसानों और मध्यम वर्गीय भाइयों का फायदा हो। मैं आपको याद दिला दूँ कि आज हालात कितने भी नाजुक क्यों न हों, आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो बातें अभी तक पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों, द्वन्द्वात्मक वस्तुवादियों और विज्ञानवेत्ताओं तक ही सीमित रहीं, ये आपको भी समझनी होंगी। आम आदमी हालांकि इन्हें जानते हैं लेकिन उन्हें शक बना रहता है, क्या सचमुच अनपढ़, गंवार और कंगाल जनसाधारण संगठित होकर वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति को जन्म दे पाएंगे? क्या कभी ऐसा संभव हो पाएगा? क्या शोषित जनता की विकल्प शक्ति को इतना अपराजेय बनाया जा सकेगा जो महाकाय दमनकारी बुर्जुआ राजसत्ता के टुकड़े-टुकड़े कर के रख दे, जो इतनी ताकतवर है, जिसके पास पूँजी और फौज की इतनी बड़ी शक्ति है? नवम्बर क्रान्ति ने इतिहास में पहली बार सारी दुनिया के सामने हकीकत में यह संभव कर दिखाया। साथ ही नवम्बर क्रान्ति ने एक और सवाल को स्पष्ट किया है जिसके बारे में लोगों के मन में संदेह बना रहता था कि जब क्रान्ति के बाद भी प्रशासन की बागडोर निहित स्वार्थी चाकरों, इन्हीं चापलूस क्लर्कों और नौकरशाहों की भीड़ के हाथों में रहेगी तो क्या उनसे कभी पिण्ड छुड़ा पाना संभव होगा। क्योंकि प्रतिक्रियावादियों के असली एजेण्ट तो वे ही हैं जो जनता के खिलाफ सारा तामझाम संभाले हुए हैं। अगर क्रान्ति के बाद भी ऐसा ही रहा तो सर्वहारा वर्ग परिवर्तन कैसे ला सकेगा? लेनिन ने बताया कि नहीं, दोनों स्थितियों में भारी अंतर है। जब राजसत्ता सही मायने में सर्वहारा के हाथ में होगी, दिखाऊ, जाली या संसदीय ताकत के रूप में नहीं, बल्कि जहाँ कृषक समितियाँ, मजदूर समितियाँ, क्रान्तिकारी सोवियतें, परिषदें राजसत्ता दखल कर लेने के बाद, निम्नतम स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर के केन्द्र तक सम्पूर्ण सत्ता का नियंत्रण करेंगी और सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी पार्टी इन परिषदों का केन्द्रीकरण और समन्वयन बनाये रखने का कार्य करेगी, यानी राजसत्ता वर्ग के तौर पर यथार्थ में जब सर्वहारा के अधीन होगी तब सर्वहारा आसानी से उन नौकरशाहों पर नियंत्रण रख पाएगा, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकने की स्थिति में होगा जो सर्वहारा प्रभुसत्ता की अवज्ञा करने की गुस्ताखी करेंगे या सर्वहारा की विचारधारा और सिद्धान्तों के अनुकूल अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में कोताही बरतेंगे।

जो अपने स्वार्थों की खातिर पार्टी कार्यकर्ताओं में अंधानुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं चाहे वे हमारी पार्टी ही में क्यों न हों, अगर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी साहित्य से बाहर कुछ भी पढ़ने देने की मनाही करती है, दूसरों के साथ चर्चा, तर्क-वितर्क करने देने से रोकती है, दूसरों के विचारों से परिचित होने देने से आनाकानी करती है तब इसका मायने यही होगा कि हम भी तमाम ऊँचे-ऊँचे आदर्श बखान करने के बावजूद, किसी भी बहाने सही, समाज के युक्तिवादी मन को ही भोथरा बना रहे हैं। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को तो क्रान्तिकारी जनसमुदाय का हरावल दस्ता कहा गया है। कम से कम उनसे यह उम्मीद की जाती है कि उनकी राजनैतिक चेतना का स्तर जनसाधारण से ऊँचा हो। उल्टे, उनकी ही युक्तिसंगत मानसिकता का लोप हो जाए तब क्या होगा? अगर वे दूसरों के मत को धैर्यपूर्वक सुनकर और बारीकी से विश्लेषण कर खारिज कर दें तो यह बात हुई। लेकिन अगर इनमें न पढ़ने और दूसरों के विचारों को न जानने की मानसिकता पनप उठे, तब क्या होगा? इससे समाज में स्तर दर स्तर कूपमण्डूकता फैलेगी, दकियानूसी विचार आसानी से घर कर जाएंगे और एक बार अगर युक्तिवादी मानसिकता ही समाज से विदा ले ले, तो इसका फायदा उठाकर समाज के ये 'ऊँचे लोग' जिनके पास धन-सम्पत्ति और राजसत्ता की ताकत है, युवाशक्ति को रिश्वत देकर अपनी ओर खींच लेंगे। इसके बाद वे युवकों को जीविकोपार्जन के अनैतिक कामों में लगाएंगे और फासीवाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अतः कोई भी हो, जो पार्टी अनुशासन के नाम पर या किसी और बहाने समाज में अंधता या कट्टरता को प्रश्रय देते हों, भले ही वे हमारी पार्टी ही में क्यों न हों, समाज के खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए अक्षम्य नहीं हैं। वे जनआन्दोलन या क्रान्ति का नेतृत्व क्या करेंगे? उन्हें जनता को गुमराह करने के इल्जाम में जनआन्दोलन के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसलिए अनुभव बताता है कि सैद्धांतिक चर्चा और वैचारिक संघर्ष के रास्ते को किसी भी मुल्क के क्रान्तिकारियों और मार्क्सवादियों ने कभी हतोत्साहित नहीं किया बल्कि संयुक्त जन आन्दोलनों में इसे करने की खुली छूट दी है। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखा है कि वाद-विवाद और विचारधारात्मक संघर्ष के चलते उसकी एकता में दरार न आने पाए, साझे दुश्मन के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में कोई व्यवधान उपस्थित न हो और वह कहीं शारीरिक बल प्रयोग के स्तर तक न पहुँच जाए। वैचारिक संघर्ष चलाते समय केवल इन्हीं बातों पर विशेष गौर किया जाना चाहिए। संयुक्त जनआन्दोलन में वैचारिक संघर्ष को प्रोत्साहित करना एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में इसी को हतोत्साहित किया जा रहा है।

यहाँ हमें एक बात और याद रखनी होगी। ये नौकरीपेशा लोग सब पैसे के एवज में अपने मालिक का काम करते हैं। इसलिए जब मजदूर-किसान उनके असली मालिक होंगे और सत्ता में होंगे तब शिक्षित तबके के बहुसंख्यक लोग क्लर्क और नौकरशाह बुर्जुआ वर्ग के तलवे न चाटकर मजदूर-किसानों का हुक्म बजाएंगे, पैसे के लिए उनकी सत्ता को स्वीकार करेंगे और नौकरी के लिए उनकी लल्लो-चप्पो करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते पाये गये तो उन्हें हटा दिया जाएगा और तब प्रशासनिक काम काज के लिए मजदूर-किसानों के बीच से ही कुशल कर्मियों को ढूँढ़ निकाला जाएगा। नवम्बर क्रान्ति ने यह साबित कर दिखाया है। बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में रूस के मजदूर-किसान सत्ता दखल के बाद नौकरशाहों के एक तबके को अपने नियन्त्रण में लाने में सफल हुए थे। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने क्रान्ति वोट के जरिए, महज सभा-जुलूसों के जरिए या डण्डेबाजी-पथराव के जरिए हासिल नहीं की थी। उनकी क्रान्ति एक महान सृजनात्मक प्रयास से, जनता की विकल्प राजनैतिक शक्ति को जन्म देने के माध्यम से हुई थी। जनता की वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति के अभ्युत्थान से हमारा अभिप्राय क्या है? हमारा आशय है मजदूर-किसानों की समितियों का गठन कर उन्हें देश भर में जाल की तरह फैलाना। ये समितियाँ अपने क्रान्तिकारी संघर्षों को परिचालित करने का औजार होंगी। स्कूल-कॉलेजों में प्रशिक्षित हुए बिना भी किसान-मजदूर संगठन की क्षमता तथा प्रतिभा हासिल कर लेंगे यानी ऐसी क्षमताएं और प्रतिभाएं जो संगठन की तमाम समस्याओं और जटिल से जटिल गुत्थियों को सुलझा सकें, उन पर निगरानी रख सकें और देशव्यापी स्तर पर संगठन को खड़ा कर सकें। इसलिए हम कहते हैं कि क्रान्तिकारी संघर्षों के जरिए जनता की वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति विकसित होती है जो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था का जिम्मा ले सकती है। मजदूर-किसान राज्य व्यवस्था नहीं चला सकते इस धारणा को भी रूस की नवम्बर क्रान्ति ने गलत साबित कर दिया। नवम्बर क्रान्ति से सबक और प्रेरणा लेकर यूरोप, चीन, वियतनाम आदि मुल्कों के मजदूर-किसानों ने अपने-अपने मुल्कों में अपनी सत्ता कायम की।

नवम्बर क्रान्ति का स्मरण करते समय जिस बात को आपको याद रखना है,वह है, मौजूदा हालात में बदलाव आकर ही रहेगा। चूँकि बुर्जुआ वर्ग शक्तिसम्पन्न है, उनके हाथों में शक्तिशाली राजसत्ता है, इसलिए वे हमारी गर्दनों में चक्की के पाट की तरह पड़े रहेंगे और हमेशा के लिए शासन करेंगे–अगर यह बात होती तो बेशक बुर्जुआ वर्ग के लिए बड़ी खुशी की बात होती, ऐसा विचार ही उनके लिए सुखदायक होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परिवर्तन कितनी शीघ्रता से आता है, यह आप पर निर्भर करेगा। क्रान्ति कितनी जल्दी होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सर्वहारा वर्ग की सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में, सही मूल राजनैतिक लाइन के आधार पर संयुक्त जनआन्दोलनों को संचालित करते हुए सोवियतों की तरह जन कमेटियों और क्रान्तिकारी परिषदों के रूप में जनता की विकल्प राजनैतिक शक्ति को कितनी तेजी से आप ढाल पाते हैं। याद रखिए, धोखाधड़ी, नारेबाजी और चुनावी धांधली के जरिए यह काम कदापि सम्पन्न नहीं होगा। क्रान्ति आप तभी कर पाएंगे जब सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में सही मूल राजनैतिक लाइन व सही विचारधारा के आधार पर आप जनता की वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति को जन्म देने के काबिल हो जाएंगे। चुनाव आप लड़ते हैं, आर्थिक मांगों को लेकर जनवादी आन्दोलन भी संगठित करते हैं, इन्हें क्रान्तिकारी संघर्षों के मूल उद्देश्य से जोड़ना होगा, उसका सहयोगी बनाना होगा, केवल तभी ये तात्पर्यपूर्ण होंगे। अन्यथा, एकदम निरर्थक। इसी के साथ-साथ आपको यह भी समझना होगा कि जिन जनआन्दोलनों को आप चला रहे हैं, उनमें बड़े उतार-चढ़ाव आएंगे, कभी वे आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे हटेंगे, कभी सफलता चूमेंगे तो कभी हारेंगे, धक्का सहेंगे। क्योंकि आन्दोलनों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा है। लेकिन मूल मुद्दे की बात यह है कि क्या आप इन आन्दोलनों के सामने सही विचारधारा, सही सिद्धान्त और क्रान्ति का सही स्तर प्रतिपादित कर पाए हैं या नहीं। यानी क्या आप सही-सही निर्धारित कर पाए हैं कि इस क्रान्ति का मूल राजनैतिक लक्ष्य बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता से उखाड़ फेंकना है जो अब साम्राज्यवादियों की जगह सत्ता में बैठा हुआ है।

भारत समाजवादी क्रान्ति के चरण में है

हमारे देश में कहाँ और कितना सामन्तवाद है, इस बात की मीन-मेख निकालने के पचड़े में नहीं पड़ें तो ज्यादा अच्छा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे देश में सामंती आर्थिक सम्बंध या उत्पादन सम्बंध कहे जाने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके अवशेष हैं जो मौजूदा समाज के ऊपरी ढांचे में आदतों, रीति-रिवाजों और नीति-नैतिकता के रूप में विद्यमान हैं। तिस पर भी तर्क की खातिर अगर यह मान भी लिया जाए, जैसा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभी भी सामंती भूमि संबंध मौजूद हैं तब भी क्या सच नहीं है कि बुर्जुआ वर्ग द्वारा नियंत्रित और निर्देशित भारतीय राजसत्ता गहराते विश्व पूँजीवादी बाजार संकट और उसके हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव के बीच जितना हो सके उतना पूँजीवाद को सुदृढ़ करने में लगी हुई है? अगर ऐसा ही है तब हमें मानना ही होगा कि भारतीय राजसत्ता निस्संदेह पूँजीवादी राजसत्ता है और यहाँ सत्तारूढ़ बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता से उखाड़ फेंककर सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता पर कब्जा करना ही क्रान्ति का मूल राजनैतिक कार्यक्रम है, यानी भारतीय क्रान्ति पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति है।

इस प्रसंग में लेनिन की एक महत्वपूर्ण सीख को याद दिलाना चाहूँगा। एकबार, राष्ट्रीय राज्य के चरित्र निर्धारण के प्रश्न को लेकर रोजा लग्ज़मबर्ग की काउत्सकी से बातचीत हुई। काउत्सकी उस समय तक गद्दार नहीं हुए थे। रोजा का मत था कि जो देश राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हैं लेकिन आर्थिक तौर पर साम्राज्यवादी देशों पर निर्भर हैं और विदेशी वित्तीय पूँजी के अधीन हैं, उन्हें स्वाधीन बुर्जुआ राज्य या राष्ट्रीय राज्य नहीं कहा जा सकता। काउत्सकी ने कहा था कि नहीं, इन राज्यों का चरित्र स्वाधीन राष्ट्रीय बुर्जुआ राज्यों का है। उपरोक्त

(शेष पृष्ठ 5 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

धारणा के आधार पर रोजा ने कहा था, नहीं, वह नाममात्र की स्वाधीनता है; अत: इन देशों की जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ बुर्जुआ वर्ग के सहयोग से अपना मूल संघर्ष निर्देशित करना होगा, जैसा कि हमारे देश में जनता की जनवादी क्रान्ति के समर्थक भी वकालत कर रहे हैं। जवाब में लेनिन ने काउत्सकी का समर्थन करते हुए कहा था कि जो सोचते हैं कि साम्राज्यवाद पर आर्थिक निर्भरता के कारण ये राज्य स्वाधीन राष्ट्रीय बुर्जुआ राज्य नहीं रहे, उन्होंने दरअसल साम्राज्यवाद के मौजूदा युग की अहमियत को ही नहीं पहचाना। वे समझ ही नहीं पाए कि सर्वहारा क्रान्ति और साम्राज्यवाद के वर्तमान युग में ऐसा होना ही स्वाभाविक है। पूँजीवाद के असमान विकास की वजह से कुछ पूँजीवादी देश आगे बढ़ गए और पूँजीवादी विश्व के अगुआ साम्राज्यवादी देश बन गए जिन पर नवोदित स्वाधीन राष्ट्रों के बुर्जुआ वर्गों का आर्थिक तौर पर निर्भर करना लाजमी ही है। उन्होंने यह भी बताया कि न केवल छोटे-छोटे बाल्कन राज्यों में बल्कि शक्तिशाली जार के रूस में भी जिसके खिलाफ साम्राज्यवादियों ने युद्ध किए, धनी यूरोपीय राष्ट्रों का जबरदस्त आर्थिक प्रभुत्व था। लेकिन इस कारण किसी ने भी जार के रूस को साम्राज्यवादियों का उपनिवेश नहीं माना बल्कि वह तो खुद ही एक किस्म का साम्राज्यवाद लागू किए था। यही क्यों, 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका आर्थिक निर्भरता के दृष्टिकोण से यूरोप का उपनिवेश था। क्या इससे यह साबित होता है कि अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम के जरिए किसी स्वाधीन राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई? साम्राज्यवादी पूँजी पर आर्थिक परवशता के कारण जो लोग स्वाधीन राज्यों को राष्ट्रीय राज्य नहीं मानते, लेनिन ने उन्हें गलत कहा है।

वे जो लेनिन के प्राधिकार (अथोरिटी) को भी नहीं मानते उन्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अमेरिका जो 19वीं सदी तक यूरोप पर आर्थिक तौर पर निर्भर था, उसने यूरोप के तमाम बुर्जुआ देशों को आर्थिक दृष्टि से अपने उपनिवेशों में कैसे तब्दील कर लिया? क्या स्वाधीनता संग्राम के बाद अमेरिका में कोई और क्रान्ति हुई थी? अगर वह स्वाधीनता संग्राम के बाद से एक स्वाधीन राष्ट्रीय राज्य या बुर्जुआ राज्य नहीं था तब यह संभव कैसे हुआ? इसलिए क्रान्ति का स्तर तय करने में या क्रान्ति के स्तर का चरित्र तय करने में या राज्य के चरित्र निर्धारण में क्या ये सब मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं कि वहाँ साम्राज्यवादी पूँजी का प्रभुत्व है या सामंतवाद का?

दरअसल इसका एक ही मतलब है। असली बात को नकार कर, अनावश्यक बारीकियों में फंस जाना। मसलन, अगर कोई क्रान्ति के स्तर का निर्धारण करने का प्रयास करते वक्त पेज पर पेज लिखता चला जाए–ओह, लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं, उनके पास चावल नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, देखो लोग किस तरह जमीन से बेदखल होते जा रहे हैं, उनके पास कितनी कम जमीनें हैं और बिहार की स्थिति नाजुक है, वहाँ मजदूरों को उचित मजदूरी भी नहीं मिल रही है, लोग भूखों क्यों मर रहे हैं, वगैरह-वगैरह और फिर विधि वत घोषणा करे कि इस सबसे लड़ने के लिए क्रान्ति करना जरूरी है–इससे मेरा आशय है यथार्थ मर्म को पकड़ने की बजाय गैरजरूरी तफसील में उलझना। प्रत्येक क्रान्ति का मूल प्रश्न राजसत्ता के वर्ग चरित्र निर्धारण से जुड़ा हुआ है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवादी पूँजी का प्रभाव कितना है, सामन्तवाद किस हद तक मौजूद है –इन अनावश्यक ब्यौरों में जो लोग फंसे रहते हैं और राजसत्ता के वर्ग चरित्र निर्धारण के मूल प्रश्न से कन्नी काट जाते हैं, मैं उन लोगों का ध्यान एक और मुद्दे की ओर खींचना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि फरवरी क्रान्ति के पश्चात जब रूस में बुर्जुआ करेंस्की सरकार कायम हो गई थी, रक्षा मंत्रालय जार के परिवार के ही एक व्यक्ति के अधीन था। जिन्हें इतिहास के क ख ग का भी ज्ञान है वे जानते होंगे कि उस समय तक रूस में सामंतवाद का जबरदस्त प्रचलन था। ये सामंत जिनका कैडेटों के साथ राजनैतिक गठबंधन था, नवम्बर क्रान्ति तक पूरे वक्त बोल्शेविकों से लड़ते रहे। राजसत्ता का वर्ग चरित्र निर्धारित करते हुए क्या लेनिन ने अपनी थीसिस में कहीं भी लिखा कि रूस बुर्जुआ जारशाही राज्य है जिसमें बड़े बुर्जुआ का वर्चस्व है? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? सिर्फ इसलिए कि बुर्जुआ वर्ग राजसत्ता में मौजूद था। और यही बुर्जुआ वर्ग सामंतवाद के साथ समझौता करता रहता था। फरवरी क्रान्ति से पहले इससे बिल्कुल उल्टा था। सामंत और राजा-नवाब सत्ता में थे जो जरूरत पड़ने पर बुर्जुआ वर्ग से कभी दोस्ती गांठते थे, कभी लड़ भिड़ जाते थे। लेकिन फरवरी क्रान्ति के बाद बुर्जुआ वर्ग सत्ता में आ गया। वे कभी सामंतवाद को आघात पहुँचाते थे तो कभी क्रान्ति की भयग्रंथी से उससे मैत्री भी कायम करते थे। लेकिन बुर्जुआ वर्ग जो भी कर रहा था वह राजसत्ता में बैठकर सत्तारूढ़ वर्ग की हैसियत से कर रहा था। इन मुद्दों पर लेनिन ने कोई गलती नहीं की। इसी कारण लेनिन ने रूसी राजसत्ता का चरित्र 'बड़े पूँजीपतियों के नेतृत्व में बुर्जुआ जारशाही सत्ता' के रूप में कभी व्याख्यायित नहीं किया। बल्कि उन्होंने ही बताया कि फरवरी क्रान्ति के बाद रूस की राजसत्ता पुराने वर्ग यानी निकोलाई जार के हाथों से एक नए वर्ग यानी रूसी बुर्जुआ वर्ग के हाथों में आ गई। इसका मतलब क्या है? यह इस बात को प्रमाणित करता है कि क्रान्ति का स्तर तय करने में बुनियादी सवाल है किस वर्ग के हाथों में राजसत्ता मौजूद है?

कोई राज्य स्वाधीन राष्ट्रीय बुर्जुआ राज्य है, हम यह कैसे निर्धारित करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए रोजा लग्ज़मबर्ग को लेनिन ने बताया कि यदि कोई तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में या विश्व पूँजीवादी बाजार के संकट और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव की पृष्ठभूमि में पूँजीवाद के सर्वाधिक उन्मुक्त, व्यापकतम व तीव्रतम विकास के लिए प्रयास करें या मेरे विचार से इसे इस तरह रखना ज्यादा उपयुक्त होगा, अपेक्षाकृत, उन्मुक्त, व्यापकतम और तीव्रतम विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, तब निश्चित तौर पर जान लीजिए कि राज्य का चरित्र पूँजीवादी है।

इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग विचार करें तो पाएंगे कि भारत में आजादी प्राप्त करने के बाद बुर्जुआ वर्ग ने राजसत्ता संभाली। भले ही हम ग्रामीण उत्पादन के चरित्र और मौजूदा भूमि संबंधों को समझने में विफल रहे और इतना ही समझ लें कि भारतीय राजसत्ता पूँजीवाद को सुदृढ़ करने के ही जी तोड़ प्रयास कर रही है, तब भी साबित हो जाएगा कि भारतीय राज्य एक स्वाधीन राष्ट्रीय राज्य है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शब्दावली में राष्ट्रीय राज्य का मतलब अर्ध-औपनिवेशिक या अर्ध-सामंती राज्य से नहीं होता बल्कि बुर्जुआ राष्ट्रीय राज्य से होता है। लेनिन के मुताबिक बुर्जुआ राष्ट्रीय राज्य का मायने होता है पूँजीवादी राज्य। अत: इसी पूँजीवादी राजसत्ता की मशीनरी को नेस्तनाबूद कर देने की क्रान्ति राजसत्ता से बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकने की क्रान्ति है और *उस हद तक और उस अर्थ में* भारतीय क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति है। किसी भी बहाने, किसी भी सिद्धांत की आड़ लेकर जो लोग इस बुनियादी सवाल को टाल जाना चाहते हैं, वे दरअसल जनता के ध्यान को गैरजरूरी तफसील की ओर ले जाना चाहते हैं और भारतीय क्रान्ति की सही मूल राजनैतिक लाइन के सवाल पर भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं। इसी कारण, जब देश में क्रान्तिकारी जन आन्दोलन का एक व्यापक उभार पैदा होगा, तब वे काल्पनिक दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाइयाँ निर्देशित करते हुए अपनी ऊर्जा का अपव्यय करेंगे। या, इसके विपरीत, प्रतिक्रियास्वरूप वे निरापद संसदीय राजनीति में शरण और सुरक्षा ढूँढ़ेंगे। इन दोनों संभावित घटनाओं में से एक न एक होकर ही रहेगी। संसदीय राजनीति के निरापद और निश्चित आश्रय की शरण लेते हुए संशोधनवादी-सुधारवादी गुट में शामिल होना अथवा क्रान्तिकारी जोश को दुस्साहसिकता की मार्फत ठण्डा कर देना, बस सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं उनके लिए।

वैचारिक संघर्ष संयुक्त जन-आन्दोलन की निहायत जरूरी शर्त है

अगर मूल राजनैतिक लाइन ही गड़बड़ रहे तो कौशलगत मुद्दों जैसे जनवादी जन-आन्दोलन को संचालित करने का उद्देश्य, नजरिया और शैली आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही और वे भी गड़बड़ा जाएंगे। आज तमाम मांगों को लेकर जो जनआन्दोलन गठित किए जा रहे हैं, मसलन, खाद्यान्न और जमीन देने, जमीन से गरीब किसानों की बेदखली रोकने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, विदेशी पूँजी की जब्ती की मांग वगैरह यदि इन जनवादी आन्दोलनों का मूल लक्ष्य पूँजीवादी राजसत्ता को उखाड़ फेंकना न हो, तब उनका कौशलगत रुख, तौर-तरीका, नीतियाँ और सिद्धान्त, संघर्ष के सही वक्त का चुनाव, वर्ग-विन्यास, कार्यक्रम वगैरह सब भिन्न किस्म के होंगे। अत: इस प्रसंग में मैं एक और बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। संयुक्त आन्दोलन में हमें बहुत गलत समझा गया है। हम लोग संयुक्त आन्दोलन के हामी हैं। संयुक्त आन्दोलन में हम सब दल अपनी-अपनी मूल राजनैतिक लाइन को लेकर शामिल होते हैं। मूल राजनैतिक लाइनों के बीच फर्क संयुक्त आन्दोलन के कार्यक्रम में परिलक्षित होता है। इसलिए हम लोगों के बीच आन्दोलन के लिए सही समय चुनने, उसके रणकौशल, राजनैतिक लक्ष्य-उद्देश्य को लेकर और कैसे आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाए और किस राजनैतिक दृष्टिकोण से उसे विकसित किया जाए, इन बातों को लेकर तफर्का लाजमी है। विचारधारा और मूल राजनैतिक लाइन को केन्द्र कर अगर संयुक्त आन्दोलन में कुछ मतभेद पैदा हो रहे हैं तो हम उस पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए लोग बाग हमें एकता-विरोधी करार देते हैं।

वे मित्रगण जो कहते हैं कि संयुक्त आन्दोलन में आलोचना करने से एकता भंग होती है, मेरी राय में एकता-संघर्ष-एकता के सिद्धांत के बारे में उनका नजरिया सही नहीं है। चीन की 10वीं पार्टी कांग्रेस में इसी सिद्धांत को फिर दोहराया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरी एकता, कोई संघर्ष नहीं या पूरा का पूरा संघर्ष, कोई एकता नहीं – एकता की ऐसी अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। जो लोग कहते हैं कि संयुक्त जन-आन्दोलन से आलोचना करने से एकता में दरार पैदा होती है, वे भूल जाते हैं कि जब संयुक्त आन्दोलन में हम उनकी चालों का विरोध कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ गंभीरता के साथ एकता की आवश्यकता पर भी भारी जोर देते हैं और बार-बार उसकी संभावनाओं पर विचार करते हैं। हमारी राय में एकता-संघर्ष-एकता के बारे में यही सही दृष्टिकोण है। इसलिए जन आन्दोलन संचालित करने के दौरान इस तरह के सवालों पर मतभेद जैसे, आन्दोलन में कौशलगत दाँवपेंच, आन्दोलन करने का समय, मांगें रखने का तरीका, आन्दोलन को चलाने की शैली, लक्ष्य-उद्देश्य, कहाँ तक आन्दोलन को ले जाना है आदि मसलों पर अपनी-अपनी राजनैतिक लाइनों में फर्क के चलते मतभेद रहना स्वाभाविक ही है। चूँकि आन्दोलन का कार्यक्रम एक है, इन मुद्दों पर कोई मतभेद नहीं होगा –ऐसा कभी नहीं होता। उदाहरण के लिए हम में से जो संयुक्त आन्दोलन चला रहे हैं, हम सब पूँजीवाद और पूँजीपति वर्ग की पार्टी, कांग्रेस को अपना मुख्य दुश्मन समझते हैं। अन्यथा हम संयुक्त संघर्ष छेड़ते क्यों हैं? जो पूँजीवाद को मुख्य दुश्मन नहीं मानते, वे संयुक्त संघर्ष में शामिल नहीं होते। अत: पूँजीवाद के खिलाफ लड़ाई इन आन्दोलनों में आम सहमति का मुद्दा है। लेकिन क्या यह भी सही नहीं है कि पूँजीवाद के खिलाफ इस लड़ाई के दाँवपेंचों को लेकर अलग-अलग मूल राजनैतिक लाइनों के अनुसार हम लोगों में मतभेद भी हैं?

हम सब लोग मिलकर पूँजीवाद-विरोधी संघर्ष के मूल उद्देश्य-लक्ष्य को सामने रखकर, एक आम सहमति के कार्यक्रम के आधार पर एक संयुक्त जन आन्दोलन चला रहे हैं। संयुक्त जन-आन्दोलन के भीतर ही वे तमाम प्रवृत्तियाँ और धाराएं छुपी हुई हैं जिनसे मूल लक्ष्य से भटक जाने का पूरा खतरा है। तब निरन्तर वैचारिक संघर्ष चलाए बिना संयुक्त जनान्दोलन को हम कैसे बचा पाएंगे?

अगर हम संयुक्त जनान्दोलनों की हिफाजत नहीं कर पाए तो लोग बेशक कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, बेशक वे कुर्बानियाँ भी देंगे लेकिन उनके ये संघर्ष निष्फल जाएंगे। इसीलिए स्टालिन ने जोर देते हुए कहा है कि अगर बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता के उखाड़ फेंकना है तो सर्वहारा संयुक्त मोर्चे और जनवादी आन्दोलनों के स्तर पर जनवादी संयुक्त मोर्चे के तहत जितने भी कानूनी और गैर-कानूनी जायज जनान्दोलन चलाए जा रहे हैं और उन्हें समन्वित करने के लिए स्तर-स्तर पर जो क्रान्तिकारी संघर्ष छिड़े हुए हैं, उनमें से सामाजिक जनवादी ताकतों (सोशल डैमोक्रेटिक फोर्सेस) का

(शेष पृष्ठ 6 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति ...

(पृष्ठ 5 का शेष)

पर्दाफाश करते हुए अलग-थलग करने और परास्त करने के लिए तीव्र और अनवरत वैचारिक संघर्ष चलाया जाना अत्यावश्यक होगा। अन्यथा पूँजीवाद को उखाड़ फेंका नहीं जा सकता। क्रान्ति अगर पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं है तब वैचारिक संघर्ष को एक बिल्कुल ही दूसरी ताकत के खिलाफ संचालित करना होगा। मसलन, साम्राज्यवाद-विरोधी संयुक्त आजादी आन्दोलन में जिसमें बुर्जुआ वर्ग भी शामिल है, वहाँ वैचारिक संघर्ष राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की मुख्यधारा से उसके प्रभाव को हटाने के लिए चलाया जाएगा। अगर बुर्जुआ वर्ग राजसत्ता में है तो वैचारिक संघर्ष सामाजिक जनवादी ताकतों के खिलाफ निर्देशित किया जाएगा क्योंकि सामाजिक जनवादी ताकतें यानी पूँजी और श्रम के बीच समझौता करवाने वाली ताकतें जो समाजवाद और मार्क्सवाद का ढिंढ़ोरा पीटती हैं लेकिन असलियत में समाजवादी या मार्क्सवादी होने का स्वांग भर रचती है, संयुक्त आन्दोलन को भीतर से कमजोर कर रही हैं। जो पूँजी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्हें स्टालिन की यह बात याद रखनी चाहिए, ''सामाजिक जनवाद को खत्म किए बिना पूँजीवाद को खत्म करना असम्भव है।'' यानी उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पूँजीवाद-विरोधी आन्दोलन के तहत संयुक्त आन्दोलनों में मौजूद विभिन्न रुझानों और प्रवृत्तियों को, जो कि आन्दोलन में ही छिपे तौर काम करती रहती हैं और पूँजी व श्रम के बीच समझौता कराके आन्दोलन को नाजुक क्षणों में गुमराह करने की चेष्टा करती हैं, अगर उन्हें तीव्र वैचारिक संघर्ष के जरिए अलहदा कर परास्त नहीं किया गया और मजदूर वर्ग को उनके प्रभाव से मुक्त नहीं किया गया तो पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति कभी सफल अंजाम की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा है कि पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति का यह एक महत्वपूर्ण रणनैतिक पहलू है। जो स्टालिन की अवधारणा के इस मर्म को पकड़ सकते हैं, जो समझते हैं कि संघर्ष में ही विभिन्न (सामाजिक जनवादी) प्रवृत्तियाँ और धाराएं छुपी हुई हैं, वे भलीभांति समझ सकते हैं कि क्यों हम वैचारिक संघर्ष पर इतना जोर देते हैं, क्यों हम कौशलगत दाँवपेंच पर इतना लड़ते हैं और क्यों हम संयुक्त आन्दोलन में नीति-सिद्धान्त और मूल राजनैतिक लाइन के लिए मरे जाते हैं। न तो किसी दुर्भावना से हम ऐसा करते हैं और न ही हम दुर्भावना फैलाना चाहते हैं। वैचारिक संघर्ष के दौरान कभी-कभी वे शायद हमारी कुछ बातों का बुरा मान जाएं लेकिन हमारा उद्देश्य कटुता या दुर्भावनाओं को बढ़ावा देना निश्चित ही नहीं है। वास्तव में हम आन्दोलन की एकता चाहते हैं, दूसरों के साथ दोस्ताना रिश्ते के इच्छुक हैं और एक दूसरे को जानना-समझना चाहते हैं। इसीलिए हम दूसरों की गलतियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि यदि हमारी भी कोई गलतियाँ हों तो वे हमें दिखाएं। इस तरीके से एक दूसरे की गलतियाँ दिखाने में हम परस्पर मदद कर सकते हैं और अच्छा हो, यह वैचारिक संघर्ष खुल्लमखुल्ला हो, संयुक्त आन्दोलन में शामिल हो रहे लोगों के सामने हो ताकि वे स्वयं देख पाएं कि कौन-सी लाइन सही है और कौन-सी गलत, कौन सही तर्क कर रहे हैं और कौन गलत, कौन संदर्भ रहित उद्धरण पेश करने के जरिए मूल मुद्दे को गफलत में डाल रहे हैं और कौन सत्य को उजागर करने के लिए कष्टसाध्य परिश्रम कर रहे हैं। जनसाधारण को स्वयं विचार करने का अवसर प्रदान करना संयुक्त जनान्दोलन की निहायत जरूरी और प्रधान शर्त है। नवम्बर क्रान्ति के इस सबक को हमें ग्रहण करना चाहिए।

क्रान्ति की तीन आवश्यक शर्तें

नवम्बर क्रान्ति से जो सबक हमें हासिल होता है वह है कि क्रान्ति की सफलता के लिए तीन आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिएं। पहली, एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त, विचारधारा और मूल राजनैतिक लाइन के आधार पर जनसाधारण को नेतृत्व देने लायक पर्याप्त एवं आवश्यक संगठनात्मक क्षमता रखने वाली सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी पार्टी का आविर्भाव। इस मूल मुद्दे को नजरअंदाज कर और मूल राजनैतिक लाइन के महत्व को कम आंक कर जो केवल पार्टी की संगठनात्मक ताकत को ही विशेष महत्व देते हैं वे दरअसल मूल प्रश्न को ही गड्डमड्ड कर डालते हैं। इस पर मैं पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस के अनुभव का हवाला देते हुए बता चुका हूँ। लेनिन की सीखों और विश्व साम्यवादी आन्दोलनों के इतिहास में इस सत्य को बार-बार उजागर किया गया है।

क्रान्ति की दूसरी आवश्यक शर्त है, संयुक्त मोर्चा। जनवादी आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में वाम-जनवादी ताकतों के संयुक्त मोर्चे का गठन और इस दौर के पूर्ण हो जाने पर सर्वहारा संयुक्त मोर्चे को जन्म देना जो पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति के लिए जरूरी होगा।

क्रान्ति की तीसरी आवश्यक शर्त है : संयुक्त जन आन्दोलनों या संयुक्त संघर्षों के जरिए जनता के संघर्ष के हथियार, जनकमेटियों को जन्म देना यानी जनता की विकल्प राजनैतिक शक्ति को जन्म देना जो म्यूनिसिपल कमेटियों या संयुक्त मोर्चे में शामिल राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित स्थानीय और जिला कमेटियों से एकदम भिन्न होंगी। ये संगठन बहुत कुछ रूस के मजदूर-किसानों की सोवियतों जैसी होंगी जो किसान-मजदूरों के संयुक्त संघर्षों के जरिए रूस में विकसित हुई थी। इन संगठनों के पास पर्याप्त सामर्थ्य और अधिकार होंगे कि वे कार्यक्रमों को चाहें तो स्वीकार करें या रद्द कर दें या कार्यक्रमों को ठोस व स्वतंत्र रूप से अमल में लाने की पहलकदमी करें। जब तक क्रान्ति की ये तीन आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, आन्दोलन पर आन्दोलन होते रहेंगे, लाखों लाख लोग उनमें बार-बार हिस्सा लेते रहेंगे, कुर्बानियाँ देते रहेंगे, पर क्रान्ति नहीं होगी। क्रान्ति और विद्रोह या विक्षोभ एक ही चीज नहीं हैं। क्रान्ति से हमारा अभिप्राय है, सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी राजनैतिक लाइन और सही विचारधारा के आधार पर सुनिश्चित मूल राजनैतिक उद्देश्य-लक्ष्य के साथ जनता का सचेत, संगठित और सशस्त्र अभ्युत्थान। जनता जितनी ज्यादा इन शर्तों को पूरा करती जाएगी, भारत की मौजूदा स्थिति में कायापलट के आसार भी उतने ही दैदीप्यमान होंगे और उतना ही तात्पर्यपूर्ण होगा हमारे जीवन में नवम्बर क्रान्ति की वर्षगांठ को मनाना। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ।

डी.एस.ओ. का 5वां गुना जिला छात्र सम्मेलन संपन्न

गुना में छात्र सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए एआईडीएसओ के अखिल भारतीय महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा

गुना (म.प्र.) : छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के पाँचवें गुना जिला छात्र सम्मेलन का खुला अधिवेशन 12 अक्टूबर को लक्ष्मीगंज गुना में संपन्न हुआ। हालाकिं लक्ष्मीगंज गुना में सम्मेलन, रैलियां, सभाएं तो पहले भी बहुत हुई हैं, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति इतना समर्पित, इतना अनुशासित व इतना जोश-खरोश से भरा हुआ कार्यक्रम इससे पहले नहीं देखा गया। लक्ष्मीगंज में हुए खुले अधिवेशन में उपस्थित विशाल छात्र समूह ने शहर के बुद्धिजीवियों व शिक्षा प्रेमी जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। छात्र सम्मेलन में उपस्थित छात्रों की इतनी बड़ी संख्या व कार्यक्रम की व्यवस्था और छात्र-छात्राओं के अनुशासन को सभी ने सराहा।

सम्मेलन में गुना जिले, अशोकनगर जिले ,आरोन, बीनागंज, कुंभराज, बमोरी, व आस-पास के गाँवों, तहसीलों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए। खुले अधिवेशन में मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई.(सी) के दिल्ली राज्य कमेटी सचिव कॉ. प्रताप सामल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम सरकारें फीस वृद्धि करके एवं शिक्षा को देशी-विदेशी पूँजीपतियों के हाथों में देकर करोड़ों गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्रों को शिक्षा से वंचित कर रही हैं। शिक्षा को बचाने के लिए संगठित छात्र आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है।

इस अवसर पर ऑल इंडिया डी.एस.ओ के अखिल भारतीय महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा ने छात्रों को संबोधित करते हुये कहा कि जिस सर्व सुलभ जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का सपना आजादी आंदोलन के मनीषियों, शहीदों ने देखा था वह आज भी अधूरा है। शहीदों और मनीषियों के सच्चे प्रतिनिधि होने के नाते आप सभी को इस सपने को पूरा करने के लिये आंदोलन तेज करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉ भास्करानन्द, स्वागत समिति के संयोजक डॉ. श्याममोहन मिश्रा, सहसंयोजक गिरधर शर्मा, ट्रेड यूनियन से जुड़े नरेन्द्र भदौरिया जी व एसयूसीआई(सी) जिला प्रभारी कॉ. प्रदीप आर.बी. ने भी छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन जैन ने की। प्रतिनिधि अधिवेशन 13 अक्टूबर को स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में हुआ जिसमें लगभग 125 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इसमें शिक्षा व छात्र समस्याओं के खिलाफ व छात्र आंदोलन विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। सम्मेलन में 85 सदस्यीय जिला परिषद का भी गठन किया गया जिसमें कॉ. योगेश धाकड़ जिला अध्यक्ष व कॉ. अजीत सिंह पंवार जिला सचिव चुने गये।

शहीद प्रीतिलता वादेदार स्मृति सभा

इलाहाबाद (उ.प्र) : 14 अक्टूबर को आजादी आन्दोलन की प्रथम महिला शहीद प्रीतिलता वादेदार को याद करने के लिये अल्लापुर के लोहा पार्क में एआईएमएसएस के द्वारा स्मृति सभा की गई। हुदहुद चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद महिलाओं ने अपने घर से बाहर निकल कर कार्यक्रम में बहुत उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरूआत क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति से हुई। इसके उपरान्त प्रीतिलता की प्रासंगिकता और आज महिलाओं की समाज में भूमिका विषय पर चर्चा हुई।

चर्चा में, ज्ञानशीला शर्मा, लता शर्मा, इन्दु शर्मा, रश्मि मालवीय ने अपनी बात रखी। इन्दु सिन्हा ने भ्रूणहत्या पर स्वरचित बहुत मार्मिक कविता का पाठ किया। अंत में शिबांकर राय के द्वारा हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकार पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' की कहानी 'मां कैसे मरी' पर आधारित एक अतिमार्मिक और क्रांतिकारी नाटक का मंचन किया गया। रश्मि मालवीय ने धान्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की परिस्थिति में महिलाओं को संगठित करने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन झरना मालवीय ने किया।

महिला सम्मेलन आयोजित

दतिया (म.प्र.) में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों, अपराध, अश्लीलता व नशाखोरी के खिलाफ 14 सितम्बर को यहां ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें काफी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

श्रमिक–कर्मचारियों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन

पटना (बिहार) : केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में एकतरफा मजदूर–विरोधी संशोधन किये जाने के खिलाफ तथा महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी दूर करने, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विनिवेशीकरण पर रोक लगाने, सभी असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने, 15 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन करने, सभी वरिष्ठ मजदूरों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेन्शन देने, कन्ट्रेक्ट/दिहाड़ी, स्कीम वर्कर्स की सेवा नियमित करने, 45 दिनों में ट्रेड यूनियनों का गारंटी पंजीयन करने आदि मांगों को लेकर श्रमिक–कर्मचारियों का राज्य स्तरीय कन्वेंशन 18 अक्टूबर को राजधानी के आई.एम.ए. हॉल में आयोजित हुआ। कन्वेंशन का आयोजन बिहार श्रम संगठन मंच के तत्वावधान में किया गया, जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध प्रदेश की करीब–करीब सभी ट्रेड यूनियन, औद्योगिक महासंघ, बैंक व बीमा सहित केन्द्र एवं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के संगठन शामिल थे।

कन्वेंशन के विशिष्ट अतिथि एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के. एल. गुप्ता ने कहा कि जिन पार्टियों के मजदूर संगठनों द्वारा यह कन्वेंशन आयोजित किया गया है, उनमें से अधिकांश केन्द्र या विभिन्न राज्यों की सत्ता में रह चुकी हैं अथवा अब भी हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आजादी के 68 सालों बाद भी आज मजदूरों के हक–हकूक की लड़ाई मजबूत होने की बजाय और कमजोर हुई है। वर्ग विभाजित समाज में सरकार की नीतियां वर्ग निरपेक्ष नहीं होतीं। वे या तो मजदूर वर्ग के हित में होती हैं, या फिर वे मालिक वर्ग के हितों की हिफाजत करती हैं। जाहिर है आजादी के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा देश में लागू नीतियों ने मालिक–पूंजीपति वर्ग को फलने–फूलने का मौका दिया है, जबकि मजदूरों की हालत बद से बदतर हुई है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी मजदूरों को पेन्शन दी जाती थी, लेकिन आज उसे खत्म किया जा रहा है। मजदूरों से आठ घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है। श्रमेव जयते के नारे की आड़ में मजदूरों के श्रम को निचोड़ा जा रहा है। मजदूरों के श्रम को निचोड़कर उनकी हालत ऐसी बना दी गयी है कि वे 45–50 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं। कॉमरेड गुप्ता ने कहा कि मजदूरों को उनके हक–अधिकार से परिचित कराना और उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष का सही रास्ता दिखाना नितांत आवश्यक है। सही रास्ते और सही दृष्टिकोण के बगैर मजदूर अपनी लड़ाई को मंजिल तक नहीं ले जा सकते।

कन्वेंशन का उद्घाटन सीटू की राष्ट्रीय सचिव के. हेमलता ने किया। कन्वेंशन का मूल प्रस्ताव एआईटीयूसी के चक्रधर प्रसाद सिंह ने पेश किया जबकि संचालन एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष अरूण कुमार सिंह, एआईटीयूसी के जानकी पासवान, आईएनटीयूसी के चन्द्र प्रसाद सिंह, यूटीयूसी के अमेरिका महतो, सीटू के राजकुमार झा, एचएमएस के अघूनू यादव, बीएमएस के अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव, एआईसीसीटीयू के श्याम लाल द्वारा गठित अध्यक्ष मंडल ने किया। कन्वेंशन को सीटू के गणेश शंकर सिंह, एआईयूटीयूसी के मो. इदरीश, एआईटीयूसी के कपिल यादव, एआईसीसीटीयू के आर एन ठाकुर, यूटीयूसी के वीरेन्द्र ठाकुर, बीएमएस के अविनाश प्रसाद श्रीवास्तव, एचएमएस के अघुनू यादव, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राजबली प्रसाद, नवल किशोर राय, जेपीए के अरूण कुमार, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मी संघ के नरेश राम, बीईएफआई के रामलला, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के रामाकांत अकेला, खेत मजदूर सभा के गोपाल रविदास तथा निर्माण मजदूर संघ के नाथुन जमादार ने भी संबोधित किया।

5 दिसम्बर 2014 को राजधानी पटना में संयुक्त विशाल रैली कर प्रतिरोध दिवस मनाने का आह्वान कन्वेंशन द्वारा किया गया।

पटना में राज्य स्तरीय कन्वेंशन में शामिल श्रमिक–कर्मचारी व नेतागण

प्रभाष घोष का वक्तव्य ... पृष्ठ 2 का शेष)

बंगाल में स्थिति ऐसी है कि जमीनी स्तर पर हमारे और आपके कार्यकर्ताओं का सम्बंध अच्छा नहीं है। वहाँ कड़ुवाहट है। अत: सर्वव्यापक एकता कहने से जो समझा जाता है वह अखिल भारतीय स्तर पर संभव है अभी पश्चिम बंगाल में संभव नहीं है। यहाँ हमें धीरे–धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा। अब मुद्दों पर आधारित संयुक्त प्रोग्राम हम ले सकते हैं। जैसे साम्राज्यवाद–विरोधी, साम्प्रदायिकता–विरोधी कार्यक्रम। इसके आधार पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच जितनी आपसी समझ बढ़ेगी, उतनी ही एकता भी धीरे–धीरे प्रसारित होती रहेगी। मैंने उनको बताया कि 1 नवम्बर को दिल्ली में हो रही बैठक में हमारे प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वार्तालाप के अंत में मैंने दोहराया कि जुझारू वर्ग संघर्ष और जन संघर्षों के बिना वामपंथी ताकतें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। यही है सीपीआई(एम) के साथ हमारी बैठक का संक्षिप्त विवरण

संवाददाताओं के सवालों के जवाब

रिपोर्टर: आपका यह वक्तव्य सुनकर प्रकाश करात ने क्या कहा?

प्रभाष घोष: उन्होंने चुपचाप सुना, कोई टिप्पणी नहीं की। विमान बोस ने भी चुपचाप सुना।

रिपोर्टर: आपकी और सीपीआई(एम) की मुख्य शक्ति तो पश्चिम बंगाल और केरल में है। यदि इन दो राज्यों में आप व्यापक एकता नहीं कायम करते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर यह कैसे सफल होगी?

प्रभाष घोष: केरल और पश्चिम बंगाल में उनकी भी शक्ति है, हमारी भी शक्ति है। इन दो राज्यों को छोड़कर कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, यू.पी., दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश आदि लगभग सभी राज्यों में हमारा संगठन अच्छा ही है और यह बढ़ रहा है। मैंने प्रकाश करात को यह भी बताया कि अभी हिमाचल प्रदेश, मणीपुर और नागालैण्ड, मिजोरम इसी तरह के कुछ राज्यों को छोड़कर अन्यान्य लगभग सभी राज्यों में हमारा काम हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जानकारी उन्हें हैं। इसके अलावा भी उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानकारी है कि हम अब कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल राहत शिविर चला रहे हैं। इसलिए संक्षेप में, अखिल भारतीय स्तर पर और इन राज्यों में सर्वव्यापक एकता होगी। बंगाल में कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए धीरे–धीरे इसे हासिल किया जाएगा। एकमात्र केरल में ही सीपीआई(एम) के साथ कोई एकता नहीं होगी। आज की हमारी बातचीत सकारात्मक रही, घोषणा के प्रारूप को सभी का विचार जानने के बाद 1 नवम्बर को दिल्ली में अंन्तिम रूप दिया जाएगा।

रिपोर्टर: क्या आप पश्चिम बंगाल में राज्य व केन्द्र सरकारों के खिलाफ आन्दोलन करेंगे?

प्रभाष घोष: करेंगे का मतलब!! हम तो केन्द्रीय और राज्य सरकारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों मे लगातार आन्दोलन करते ही जा रहे हैं। मीडिया में ये सब खबरें नहीं दिए जाने पर भी आप पत्रकार लोग तो निश्चित ही जानते हैं। हमारी पार्टी के प्रकाशनों को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ कितने आन्दोलन कर रहे हैं।

भगत सिंह जयंती पर आयोजित कार्यक्रम

नाँगलकलां (सोनीपत): 28 सितम्बर को नाँगल कला गाँव में शहीद भगतसिंह जयन्ती पर मशाल जुलूस निकाला गया। इससे पहले शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद हुई सभा को सम्बोधित करते हुए एआईडीवाईओ सोनीपत जिला कमेटी के अध्यक्ष कॉ. देवेन्द्र और एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष कॉ. भास्करानन्द ने शहीद भगतसिंह के विचारों और जीवन–संघर्ष पर प्रकाश डाला। सभा स्थल पर शहीद भगत सिंह की उद्धरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

फरीदाबाद : 28 सितम्बर को शहीदे आजम भगतसिंह की 107वीं जयंती पर एनआईटी न. 5 स्थित भगतसिंह चौक पर एआईडीवाईओ की ओर से जन सभा की गई। संगठन के संयोजक डॉ. जेपी गौड़, एआईयूटीयूसी के कॉ. के.पी. सिंह, ए.के. रावत, जोरावर सिंह, अनुज, आशुतोष आदि ने वहां पर स्थित शहीद की प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण किया। उन्हें याद करते हुए आजादी आन्दोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। सभा स्थल पर क्रान्तिकारियो व प्रगतिशील लेखकों की उद्धरण–प्रदर्शनी भी लगाई गई। कॉ. ए.के. रावत ने कहा कि वर्तमान बीजेपी–नीत केन्द्र सरकार देश के विकास का नारा देकर देशी–विदेशी पूँजीपतियों के स्वार्थ में बैंक, बीमा, रेलवे और यहां तक कि रक्षा उत्पादन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) को आने का अवसर दे रही है। श्रम कानूनों को हल्का करने जा रही है। आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा कर जनता पर आर्थिक हमले कर रही है। साम्प्रदायिकता फैला रही है। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह केवल शासक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के ही नहीं बल्कि उनकी जगह देशी पूँजीपतियों का राज कायम होने और उनके द्वारा जनता का शोषण किये जाने के भी खिलाफ थे। उन्होंने नौजवानों से शोषणमुक्त समाज बनाने के भगत सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आगे आने और अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर तरह के शोषण–जुल्म के खिलाफ जन आन्दोलनों में बढ़चढ़ कर शामिल होने का आह्वान किया।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) : ए.आई.डी.एस.ओ. जिला इकाई द्वारा शहीदे आजम भगत सिंह की जयंती पर 29 सितम्बर को साइन्स कॉलेज दुर्ग में की गई सभा को सम्बोधित करते हुए नीतू साहू ने कहा कि हमें शहीदे आजम भगत सिंह एवं उनके साथी क्रांतिकारियों के जीवन–संघर्षों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी आंदोलन के गैरसमझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारियों ने जिस अदम्य साहस, उन्नत चरित्र, नैतिकता का परिचय दिया वह आज भी छात्र–नौजवानों के लिए अनुकरणीय है। हमें उनसे प्रेरणा लेकर समाज में व्याप्त आम जनजीवन की समस्याओं के खिलाफ आम जनता, छात्र– नौजवानों को संगठित करते हुए जोरदार जनआंदोलन करना होगा तभी शोषण विहीन समाज का सपना जो इन क्रांतिकारियों ने देखा था, पूरा होगा। मल्टीपर्पज हायर सेकेण्डरी स्कूल दुर्ग में दिनेश चौरे, अमृत सोनी के प्रयास से हुई सभा में स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक एवं स्कूल के छात्र उपस्थित थे।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing :5 November, 2014

आशा कर्मियों का कर्नाटक राज्य कन्वेन्शन सम्पन्न

बैंगलोर : रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक कर्नाटक आशा कर्मियों के जुलूस का एक दृश्य

बैंगलोर (कर्नाटक) : अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए कर्नाटक के 30 जिलों से आई हजारों आशा कर्मी ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बद्ध कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्त्री संघ के बैनर तले एकत्रित हुई, रेलवे स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक जुलूस निकाला। एनआरएचएम के स्तम्भों के तौर पर काम कर रही आशा कार्यकर्त्रियां मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा, पिछले बजट में ही, मैचिंग इन्सेन्टिव, मुफ्त मोबाइल व सिम आदि कई सुविधाओं की घोषणा की गई हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। यह विशाल रैली और कन्वेन्शन सरकार से इन मांगों को पूरा करने की मांग के लिए ही किया गया।

ऑल इण्डिया यूटीयूसी के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा ''एकता मजदूर वर्ग का बल है। कर्नाटक की आशा कर्मियों का संघर्ष पूरे देश के मजदूर वर्ग के लिए एक प्रेरणा है। हमारे देश का मजदूर वर्ग पूंजीवादी शासन के तहत अपने जीवन के हर क्षेत्र में गहन संकट से रूबरू है। एक सही संगठन के सही नेतृत्व के तहत और संघर्ष के सही रास्ते से आपने अपनी बहुत सारी मांगें मनवाई हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका संघर्ष और भी बुलन्दियों को छुएगा और आपको इस शोषणमूलक व्यवस्था से ही मुक्ति दिलायेगा।''

ऑल इण्डिया यूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड के. राधाकृष्ण ने अन्य एक मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुए कहा ''आशा कर्मियों के सतत संघर्ष के नतीजे के तौर पर बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। देश में पहली बार कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के बराबर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक पिछले आठ महीने की बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए आशा कर्मियों ने अपनी एकता बनाये रखी और संघर्ष जारी रखा।''

कन्वेन्शन के मुख्य अतिथि जानी-मानी लेखिका डाक्टर चन्द्रकला नन्दावरा ने कहा ''दशहरे का त्यौहार अभी-अभी सम्पन्न हुआ है। इस अवसर पर पूरे देश ने नारीत्व की पूजा की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आशा कर्मियों के तौर पर कार्यरत इतनी हजार महिलाएं ग्रामीण आबादी को जो महान सेवा प्रदान कर रही हैं उसके लिए उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली मामूली सी रकम के लिए दिनोंदिन संघर्ष करना पड़ रहा है।'' उन्होंने समाज में महिलाओं पर हो रहे हर अन्याय का मुकाबला करने का आशा कर्मियों का आह्वान किया।

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की अखिल भारतीय महासचिव डा. एच.जी. जयालक्ष्मी, मेडिकल सर्विस सेण्टर की राज्य अध्यक्ष और जानी-मानी सर्जन डा. सुधा कामथ, एसयूसीआई(सी) राज्य कमेटी सदस्य श्रीमती के. उमा, ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की आन्ध्र प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड के. सोमशेखर ने भी कन्वेन्शन को सम्बोधित किया और राज्य व केन्द्र सरकार से आशा कर्मियों की मांगें तुरन्त पूरी करने का आग्रह किया। 30 जिलों से आशा कर्मियों की नेता मंच पर विराजमान थी।

अपने सम्बोधन में आशा यूनियन की राज्य सचिव श्रीमती डी. नागलक्ष्मी ने यूनियन के संघर्षों और उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी दी। कन्वेन्शन की अध्यक्षता आशा यूनियन के राज्य अध्यक्ष सोमशेखर यादगिरी ने की।

सप्ताह भर देशव्यापी प्रतिवाद अभियान चलाने का 6 वामपंथी पार्टियों ने लिया फैसला

नई दिल्ली : 1 नवम्बर को दिल्ली में सीपीआई (एम) कार्यालय ए.के. गोपालन भवन में हुई 6 वामपंथी पार्टियों– सीपीआई(एम), एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई, आरएसपी, फार्वर्ड ब्लाक, सीपीआई एमएल -लिबरेशन की बैठक के बाद निम्न संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया :

मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही कारपोरेट व हिन्दुत्ववादी ताकतों द्वारा पोषित समन्वित दक्षिणपंथी हमला हो रहा है। नवउदारवादी नीतियों को थोपने के जरिये लोगों पर हमला बढ़ गया है जो लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने जा रहा है। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं मिल रही है। हिन्दुत्ववादी ताकतें आक्रामक साम्प्रदायिक गतिविधियों का सहारा ले रही हैं। मोदी सरकार द्वारा आरएसएस और इसके घटकों को दिये जा रहे संरक्षण का मकसद शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का साम्प्रदायीकरण कर देना है। देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है।

वामपंथी पार्टियों ने निम्न मुद्दों पर 8 से 14 दिसम्बर 2014 तक सप्ताह भर देशव्यापी प्रतिवाद अभियान चलाने का फैसला लिया है : 1) मनरेगा में कटौती और इसे हल्का किये जाने के खिलाफ

2) महंगाई रोकने; दवाइयों और औषधियों के बेतहाशा बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए

3) बीमा क्षेत्र में बढ़े हुए सीधे विदेशी निवेश को रोकने के लिए

4) काले धन को बाहर निकालने हेतु कड़े कदम उठाने के लिए

5) शिक्षा, पब्लिक ब्रोडकास्टिंग मीडिया और अन्य राजकीय संस्थानों में आरएसएस और हिन्दुत्व की विचारधारा की घुसपैठ को रोकने के लिए

6) 'लव जेहाद', नरत अभियान और साम्प्रायिक प्रचार के अन्य तरीकों को बंद कराने के लिए

7) अल्पसंख्यकों व उनके अधिकारों पर हमले बंद कराने के लिए

8) महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और लिंग आधारित हर तरह के उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए

9) दलितों पर अत्याचार व जाति उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष

बैठक में भाग लेने वालों में शामिल थे : एसयूसीआई(सी) के माणिक मुखर्जी व रणजीत धर, सीपीआई(एम) के प्रकाश करात व रामचन्द्रन पिल्लई, सीपीआई के एबी वर्धन व डी राजा, सीपीआई एमएल-लिबरेशन के सपन मुखर्जी व कविता कृष्णनन, आरएसपी के क्षितिज गोस्वामी व मनोज भट्टाचार्य, ऑल इण्डिया फार्वर्ड ब्लाक के देवव्रत विश्वास।

कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती गंभीर रूप से बीमार

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती की गंभीर बीमारी की ताजा स्थिति बताते हुए 30 अक्टूबर को एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया।

कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती, उम्र 78 साल, का इलाज 14 से 27 अक्टूबर तक सेंट मार्थाज हस्पताल, बैंगलोर में चल रहा था क्योंकि वे गंभीर श्वासकष्ट से पीड़ित थे। उनका मामला सीओपीडी, हाइप्रटेंशन, हाइपोथाइराइडीज्म, परोस्टेटोमेगली, टीआईए, उम्र से जुड़े सीकेडी और डाएस्टोलिक डिस्फंक्शन का था। चूंकि मरीज की सेहत गिरती जा रही थी, इसलिए इलाज करने वाली टीम ने उनको जहां आईसीयू लगा हो वहां रेफर कर दिया। मरीज ने मूत्रावर्धकों के प्रति रेस्पोण्ड किया और तदनुसार उनको 27 अक्टूबर को एयर एम्बूलैन्स से कलकत्ता हार्ट क्लिनिक एंड हस्पताल लाया गया।

वहां उनको जाने-माने कार्डियालोजिस्ट डा. कांति भूषण बक्शी के नेतृत्व में क्रिटिकल केयर टीम ने देखा। कॉ. चक्रवर्ती का इलाज विभिन्न विभागों के जाने-माने विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं कंसलटेंट पल्मुनोलॉजिस्ट और कलकत्ता हार्ट क्लिनिक के सीसीयू इंचार्ज डा. सैबल घोष, फोर्टिज हस्पताल, कलकत्ता के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के चीफ डा. शुभानन राय, एपोलो, ग्लीनएंजेल हस्पताल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के वरिष्ट डा. देवाशीष घोष, अपोलो हस्पताल की क्रिटिकल केयर के एचओडी डा. सुरेश रामासुब्बन, आरएनटीआईआईसीएस कोलकाता के नेफरोलॉजी के चीफ डा. प्रतीक दास, शुभंकर चटर्जी, विप्लव चन्द्र व डा. नीलरत्न नइया।

गहन जांच व दूसरे कन्सलटेंट डाक्टरों से सलाह-मशविरा करने के बाद डा. के. बी. बक्शी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फोर्टिज हस्पताल में डा. शुभानन से आपातकालीन कोरोनरी एंजियोग्राफी जल्द से जल्द कराई जाये। उनको वहां स्थानान्तरित किया गया। वहां डा. शुभानन ने उनकी एनजियोग्राफी की और उनके दिल की दाहिनी कोरोनरी आर्टरी में 80 प्रतिशत ब्लोकेज पाई गई। कलकत्ता हार्ट क्लिनिक एंड हस्पताल में इलाज के दौरान कॉ. चक्रवर्ती को हार्ट फेल के बार-बार झटके आये जिनमें 30 अक्टूबर की रात वाला सबसे जबरदस्त था जिसकी वजह हृदय की रक्तधमनियों की गंभीर असमर्थता समझा गया। कॉ. चक्रवर्ती की बीमारी के लक्षणों पर काबू पाने के लिए दिल में खून की सप्लाई कम हो तब दी जाने वाली दवाई की पूरी डोज दी गई और इसीजी में पहली बार इस रोग के लक्षण पकड़ में आये। उनके मामले में प्रधान थी। उसके सही स्थान और कितनी है इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया। बाद में स्टेंट डाल दिया गया। उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है और आपरेशन के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है लेकिन अभी भी वे खतरे से बाहर नहीं हैं।

केन्द्रीय कमेटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व हमदर्दों से अपील की है कि कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती के स्वास्थ्य सुधार हेतु चिकित्सा कोष में अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दें।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की ओर से कॉ. सत्यवान द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष:011-25726631, Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com; sarvaharadrishtikon@yahoo.com